को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण 5 और 6 में दिए गए हैं। ([देखिये परिशिष्ट CXVII अनुबंध संख्या 15]

(ख) आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रादेशिक सेवा का उपग्रह आधारित टेलीकास्ट पहले ही शुरू हो गया है। तमिलनाडु में भी इसी प्रकार की सीमित सेवा शीघ्र ही शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक उड़ीसा और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को इन्सेट-सी के चालू हो जाने अर्थात सुविधाओं की उपलब्धता पर उपग्रह आधारित प्रादेशिक सेवा प्राप्त करने के लिए चुना गया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाड् और पंजाब में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर माइक्रोवेव लिंको के जरिए संबंधित कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों से जुड़े हुए हैं। कोचीन और कालीकट के टी.वी. ट्रांसमीटरों के वर्ष 1988-89 के दौरान माइक्रोवेव के जरिए दूरदर्शन केन्द्र त्रिवेन्द्रम से जोड़ दिए जाने की उम्मीद है।

(ग) यदि अतिरिक्त ट्रांसपोंडर इन्सेट 1-सी में उपलब्ध हो जाएं तो 1990 के दशक के प्रारंभ में अथवा इससे पहले इन्सेट-2 के चालू हो जाने के फलस्वरूप गुजरात में सभी टी. वी. ट्रांसमेटरों के दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद से जोड़ दिए जाने की परिकल्पना है।

पड़ोसी देशों द्वारा सांस्कृतिक आक्रमण

333. **श्री मोर्जा इर्शादबेग :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कुछ पड़ोसी देशों द्वारा अपने दूरदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक आक्रमण किये जाने के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) क्या देश के सीमावर्ती राज्यों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध कराते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाता है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) देश के कुछ सीमा क्षेत्रों में विदेशी टेलीविजन सिग्नल प्राप्त होने की सरकार की जानकारी है। अतः सातवीं योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में टेलीविजन सेवा की किए जाने पर विशेष बल दिया गया है इस प्रयोजन के लिए तैयार की गयी विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वित होने पर देश पर सीमावर्ती जिलों की लगभग 86 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन द्वारा कवर किए जाने की संभावना है।

कपास का उत्पादन

334. **श्री मोर्जा ईर्शादबेग :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कपास का कितना उत्पादन हुआ और उसके लिये कपास उत्पादकों को प्रति क्विंटल कितना मूल्य प्राप्त हुआ;

(ख) देश को जिसी आवश्यकता की अपेक्षा यह मात्रा कितनी कम या अधिक थी; और

(ग) क्या कपास उत्पादक संघ ने इस संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के साथ कपास उत्पादन के अनुमान नीचे दिये गये है :-